



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392।
No. 392।

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2004/चैत्र 31, 1926
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2004/CHAITRA 31, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(जलवायु परिवर्तन प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2004

का.आ. 515(अ)।— भारत जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूनाइटेड नेशंस प्रैमर्क कर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज) का एक पक्षकार है और अभिसमय का उद्देश्य वायुमंडल में हरितगृह(ग्रीन हाऊस)गैस सांदरणों की उस स्तर तक स्थिरता प्राप्त करना है जो कि जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवोद्धवी हस्तक्षेप को रोके ;

और अभिसमय के अंतर्गत विकसित देश की प्रति-बढ़ता को सुदृढ़ करने के लिए पक्षकारों ने 1997 में क्योटो प्रोटोकाल को अंगीकार किया जिसमें विकसित देश पक्षकार हरितगृह (ग्रीन हाऊस) गैसों के अपने उत्सर्जनों को 1990 के स्तरों से लगभग 5.2% के औसत से 2008-12 तक की अवधि तक तापस लाएं ;

और क्योटो प्रोटोकाल, विकसित देशों के लिए मात्रात्मक उत्सर्जन सीमाएं और कटौती प्रतिबद्धताओं तथा इन लक्ष्यों के अनुपालन को सुकर बनाने हेतु क्रियाविधि, उनके बारे में रिपोर्ट देने और उसका पुनर्विलोकन का उपबंध करता है और उसमें छ: हरित गृह (ग्रीन हाऊस) गैसों - कार्बनडाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रोजन ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स (HFCs), परफ्लोरो कार्बन्स (PFCs) और सल्फर हैक्साफ्लोरोइड (SF_6) की सूची दी गई है;

और भारत ने अगस्त, 2002 में क्योटो प्रोटोकाल को अंगीकार किया है और इसे अंगीकार करने का एक उद्देश्य यह भी था कि राष्ट्रीय सतत पूर्विकताओं के अनुसार स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजनाओं (जिसे उसमें उसके पश्चात् सीडीएम कहा गया है), के क्रियान्वयन की पूर्व शर्तों को पूरा किया जाए जिसके तहत् विकसित देश ऐसे विकासशील देशों में हरितगृह (ग्रीन हाऊस) गैस में कमी लाने की परियोजना के क्रियाकलाप लेगा जिनमें विकास को प्राप्त करने में सतत विकासशील देशों की

सहायता करने और अभिसमय के अंतिम उद्देश्य में योगदान देने तथा विकसित देश पक्षकारों की उनकी मात्रात्मक उत्सर्जन सीमाओं और कमी लाने की प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से हरित गृह(ग्रीन हाउस)गैस में कमी लाने की परियोजना की गतिविधियों की लागत प्रायः बहुत कम है ;

और यू एन एफ सी सी के पक्षकारों के सातवें सम्मेलन (COP-7) में यह विनिश्चय किया गया कि वे पक्षकार जो सी डी एम में भाग ले रहे हैं, उन्हें सी डी एम के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में पदाधिकरण करना होगा और सीडीएम परियोजना चक्र के अनुसार परियोजना प्रस्ताव में प्रत्येक देश के पदाधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण से स्वैच्छिक भागीदारी की लिखित रूप में स्वीकृति शामिल होनी चाहिए और इस आशय की पुष्टि भी शामिल हो कि मेजबान देश को सतत विकास प्राप्त करने में यह योजना गतिविधि सहायता प्रदान करती है ;

और केन्द्रीय सरकार, क्योटो प्रोटोकाल के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि (सीडीएम) प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 के उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि (सीडीएम) प्राधिकरण" का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

1.	सचिव (पर्यावरण एवं वन)	अध्यक्ष
2.	विदेश सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
3.	वित्त सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
4.	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
5.	सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
6.	सचिव, विद्युत मंत्रालय अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
7.	सचिव, योजना आयोग अथवा उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव (जलवायु परिवर्तन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
9.	निदेशक (जलवायु परिवर्तन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य - सचिव

॥ राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि प्राधिकरण (सीडीएम) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (viii), खण्ड (ix), खण्ड (x) और खण्ड (xi) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उपाय करेगा और उसकी धारा 5 के अधीन निदेश जारी कर सकेगा।

(ii) (क) स्वच्छ विकास क्रियाविधि कार्यपालक बोर्ड और सेवारत पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के पक्षकारों की बैठक के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त सीडीएम से संबंधित सुसंगत नियमों और प्रतिरूपात्मकताओं में निर्धारित दिशा-निर्देशों और सामान्य मानदंड के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए परियोजनाएं प्राप्त करना।

(ख) सीडीएम परियोजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में सीडीएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण और सफल क्रियान्वयन की प्रायिकता का आंकलन और उस सीमा का मूल्यांकन भी शामिल होगा जिस तक परियोजनाएं सतत् विकास के उद्देश्यों को पूरा करती हों, जिससे इससे परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(iii) (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय अतिरिक्त आवश्यकताओं की सिफारिश करना कि परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय सतत् विकास प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं और विधिक ढांचे के अनुरूप हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं स्थानीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं और मध्यस्थ व्यक्तियों से सम्यक् रूप से परामर्श किया गया है।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि उस दशा में, जब परियोजना प्रस्ताव निवेश के समान संसाधन के अनुरूप हो, उन परियोजनाओं को जिनसे उच्चतर सतत् विकास के फायदे होते हैं, और जिनके सफल होने की संभावना हो, उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि के लिए प्रतिरूपात्मकता और प्रक्रियाओं के अनुसार परियोजना प्रस्तावों में सरकारी विकास सहायता की उपयोजना शामिल नहीं है, परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय समीक्षा करना और यह भी सुनिश्चित करना कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना के बाजार परिवेश विशेषकर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रमाणित उत्सर्जन हास के अवमूल्यन में सहायक नहीं है।

(v) (क) अनुमोदित स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजनाओं एवं उनकी प्रमाणित उत्सर्जन हास क्षमता की रजिस्ट्री का रख-रखाव करना और यह सुनिश्चित करना कि उनको प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्रियाकलाप करना कि परियोजना के विकासकर्ताओं के पास स्वच्छ विकास क्रियाविधि के सभी पहलुओं से संबंधित विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है जिसमें स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना प्रस्तावों को मान्यता एवं परियोजना कार्यों की निगरानी एवं जांच जैसे कार्य करने हेतु नामित संगठनों पर डाटाबेस तैयार करना शामिल है, और

(ग) भारत में स्वच्छ विकास क्रियाविधि प्रयासों से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आंकड़े संगृहीत, संकलित एवं प्रकाशित करना ।

III राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि प्राधिकरण का सदस्य-सचिव प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें प्रस्तावों के समन्वय एवं जांच के लिए या प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने हेतु विशेषज्ञों के माध्यम से या सलाहकार संगठनों से परामर्श करके की गई परियोजना प्रस्तावों की विस्तृत जांच कराने हेतु या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर किसी परामर्शी या विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने हेतु और यूएनएफसीसीसी एवं अन्य प्राधिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समितियों या उप समूहों का गठन करना शामिल है ।

IV राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(क) तकनीकी और वृत्तिक निवेश के लिए जब भी आवश्यक हो, सरकार, वित्तीय संस्थाओं, सलाहकार संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, विधि व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य से संबंधित पदधारियों और, विशेषज्ञों को आमंत्रित करना तथा आवश्यकता के आधार पर अन्य सदस्यों को सहयोजित करना ।

(ख) स्वच्छ विकास क्रियाविधि से संबंधित मामलों के बारे में संबंधित प्राधिकरणों, संस्थाओं, व्यक्तिगत मध्यस्थ व्यक्तियों के साथ सम्पर्क करना ।

(ग) स्वच्छ विकास क्रियाविधि या सतत विकास परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे भेजे गए किन्हीं पर्यावरणीय मामलों पर विचार करना; और

(घ) परियोजनाओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांतों और मेजबान देश को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना ।

V राष्ट्रीय स्वच्छ विकास क्रियाविधि प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को तीन महीने में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 4/5/2003-सीसीसी]

आर. के. वैश्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Climate Change Division)

ORDER

New Delhi, the 16th April, 2004

S.O. 515(E).— whereas, India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the objective of the Convention is to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

And whereas, to strengthen the developed country commitments under the Convention, the Parties adopted Kyoto Protocol in 1997 which commits developed country Parties to return their emissions of greenhouse gases to an average of approximately 5.2% below 1990 levels over the period 2008-12;

And whereas, the Kyoto Protocol provides for quantified emission limitations and reduction commitments for the developed countries and mechanisms to facilitate compliance with these targets, reporting and review and it lists six greenhouse gases – Carbon dioxide (CO_2), Methane (CH_4), Nitrous Oxide (N_2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) and Sulphur hexafluoride (SF_6);

And whereas, India acceded to the Kyoto Protocol in August 2002 and one of the objectives of acceding was to fulfill prerequisites for implementation of Clean Development Mechanism (hereinafter referred to as CDM) projects, in accordance with national sustainable priorities, where-under, a developed country would take up greenhouse gas reduction project activities in developing countries where the costs of greenhouse gas reduction project activities are usually much lower with the purpose to assist developing country parties in achieving Sustainable Development and in contributing to the ultimate objective of the Convention and to assist developed country Parties in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments;

And whereas, the Seventh Conference of Parties (COP-7) to the UNFCCC decided that Parties participating in CDM should designate a National Authority for the CDM and as per the CDM project cycle, a project proposal should include written approval of voluntary participation from the Designated National Authority of each country and confirmation that the project activity assists the host country in achieving sustainable development;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute a National Clean Development Mechanism (CDM) Authority for the purpose of protecting and improving the quality of environment in terms of the Kyoto Protocol;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the “National Clean Development Mechanism (CDM) Authority” with the following composition, namely:-

1.	Secretary (Environment and Forests)	Chairperson
2.	Foreign Secretary or his nominee	Member
3.	Finance Secretary or his nominee	Member
4.	Secretary, Industrial Policy and Promotion or his nominee	Member
5.	Secretary, Ministry of Non Conventional Energy Sources or his nominee	Member
6.	Secretary, Ministry of Power or his nominee	Member
7.	Secretary, Planning Commission or his nominee	Member
8.	Joint Secretary (Climate Change), Ministry of Environment and Forests	Member
9.	Director (Climate Change), Ministry of Environment and Forests	Member-Secretary

II. The National Clean Development Mechanism (CDM) Authority shall exercise and perform the following powers and functions, namely:-

- (i) to take measures with respect to matters referred to in the clauses (viii), (ix), (x), (xii) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and may issue directions under section 5 thereof.
- (ii) (a) To receive projects for evaluation and approval as per the guidelines and general criteria laid down in the relevant rules and modalities pertaining to CDM in addition to the guidelines issued by the Clean Development Mechanism Executive Board and Conference of Parties serving as Meeting of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- (b) The evaluation process of CDM projects would include an assessment of the probability of eventual successful implementation of CDM projects and evaluation of extent to which projects meet the sustainable development objectives, as it would seek to prioritize projects in accordance with national priorities.
- (iii) (a) To recommend certain additional requirements to ensure that the project proposals meet the national sustainable development priorities and comply with the

legal framework so as to ensure that the projects are compatible with the local priorities and stakeholders have been duly consulted.

- (b) To ensure that in the event of project proposals competing for same source of investment, projects with higher sustainable development benefits and which are likely to succeed are accorded higher priority.
- (iv) Financial review of project proposals to ensure that the project proposals do not involve diversion of official development assistance in accordance with modalities and procedures for Clean Development Mechanism and also ensure that the market environment of the CDM project is not conducive to under-valuation of Certified Emission Reduction (CERs) particularly for externally aided projects.
- (v)
 - (a) To maintain a registry of CDM projects approved, and their Certified Emission Reduction potential and confirm that these have been realized.
 - (b) To carry out activities to ensure that the project developers have reliable information relating to all aspects of Clean Development Mechanism which include creating databases on organizations designated for carrying out activities like validation of CDM project proposals and monitoring and verification of project activities, and
 - (c) To collect, compile and publish technical and statistical data relating to CDM initiatives in India.

III. The Member-Secretary of the National Clean Development Mechanism (CDM) Authority shall be responsible for day-to-day activities of the Authority including constituting committees or sub-groups to coordinate and examine the proposals or to get detailed examination of the project proposals conducted through experts or by consulting organizations for consideration by the Authority or to engage or hire any consultant or specialist on contract basis on such remuneration as may be approved by the Central Government and submission of report to UNFCCC and other authorities.

IV. The National Clean Development Mechanism (CDM) Authority shall have power

- (a) to invite officials and experts from Government, financial institutions, consultancy organizations, non-governmental organizations, civil society, legal profession, industry and commerce, as it may deem necessary for technical and professional inputs and may co-opt other members depending upon need.
- (b) to interact with concerned authorities, institutions, individual stakeholders for matters relating to CDM.

- (c) to take up any environmental issues pertaining to CDM or Sustainable Development projects as may be referred to it by the Central Government, and
- (d) to recommend guidelines to the Central Government for consideration of projects and principles to be followed for according host country approval.

V. The National Clean Development Mechanism (CDM) Authority shall furnish report about its activity at least once in three months to the Central Government.

[F. No. 4/5/2003-CCC]

R. K. VAISH, Jt. Secy.